भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4328

उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025 (बुधवार)

05 चैत्र, 1947 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास

4328. श्री सुखदेव भगतः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद विशेषकर बाढ़ प्रबंधन और अवसंरचना विकास संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा करने के लिए केन्द्रीय बजट 2024-25 की आलोचना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त बजटीय आवंटनों के बावजूद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना और आपदा प्रबंधन के लिए संतुलित विकास किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। जलशक्ति मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीम "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक पूर्वोत्तर राज्यों की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 2,382 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एफएमबीएपी स्कीम के तहत पूरे देश के लिए 400 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता रखी गई, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 121.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक कुल 208 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

पिछले 7 वर्षों (वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24) में एनईसी की स्कीमों के तहत बाढ़ को नियंत्रित करने और कटाव को रोकने में योगदान देने के लिए 62.85 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इसके अलावा, 2017 में "बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से माजुली द्वीप की रक्षा" नामक एक परियोजना 207 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी।

*****